5 मार्च, 2018

अस्ताना प्रक्रिया और सीरियाई संकट के शांतिपूर्ण समाधान का भविष्य: स्थिति पर एक नोट

*डॉ इन्द्राणी तालुकदार एवं डॉ ओमैर अनास**

सीरियाई संकट क्षेत्रीय शतरंज की एक गतिरोध है जहां विश्व शक्तियां , अमेरिका और रूस , और शक्तिशाली क्षेत्रीय खिलाड़ियों के पास मौजूद विकल्प समाप्त हो चुके हैं और उन्होंने अपने विकल्पों से परे देखना शुरू कर दिया है। रूस और ईरान की सैन्य मदद से बशर अल असाद ने क्षेत्र और सैन्य जीत के मायनों में अपनी खोई जमीन को वापस पा लिया है; अमेरिका समर्थित कुर्द समूह हसखा के पूर्वी प्रांत के सबसे स्थिर बल बने हुए हैं; और, अन्य विपक्षी समूहों, जैसे कि मुक्त सीरियाई सेना ने अलेप्पो खोने के साथ-साथ अपना बड़ा आधार भी खो दिया है। अब, देश को बड़े पैमाने पर आईएसआईएस से मुक्त घोषित कर दिया गया है, रूस ने अपने संवाद मंच - अस्ताना - के माध्यम से राजनितिक समझौते का रास्ता चुना है, जहां रूस द्वारा समर्थित विपक्ष और शासन अमेरिका और तुर्की समर्थित विपक्षी समूहों के साथ बैठक करने में सक्षम हैं। इस बीच, तुर्की ने अपना खेल बदल दिया है, सीरिया में शासन बदलने के लिए आगे बढ़ने के बजाय सीरिया के साथ इसकी दक्षिणी सी माओं में कुर्दियों का नियंत्रण कमजोर कर रहा है, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में 30,000 मजबूत सीमा बल बनाने की घोषणा की है --एक ऐसी चाल जिसे अन्य सभी अभिकर्ताओं , जैसे कि रूस, तुर्की, ईरान और असाद शासन ने प्रबलता से खारिज कर दिया है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरम्भ की गई जिनेवा शांति प्रक्रिया अब तक विफल रही है, इसलिए रूस ने जिनेवा प्रक्रिया के साथ होड़ में नहीं तो कम से कम उसके अनुपूरक के रूप में अपनी शांति प्रक्रिया - अस्ताना संवाद - आरम्भ किया है। इन दो शांति प्रक्रियाओं के मध्य, विश्व की शक्तियां और क्षेत्रीय अभिकर्ता संकट के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर सीरिया में अपना-अपना

संबंधित हित सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष में जुटे हैं। इस पत्र में चर्चा की गई है कि किस तरह अस्ताना संवाद फिर से सीरिया संकट के नतीजें बदल रहा है।

सीरिया में संघर्ष करने वाले पक्षों का युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समझौते पर नहीं पहुंच पाने के बाद 21-22 दिसंबर 2017 तक अस्ताना का आठवां दौर हुआ था। ये आठवां दौर तब शुरू हुआ जब रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन ने आधे रूसी सैनिकों को सीरिया से वापस आने का आदेश दिया।

इस बैठक में, रूस, ईरान और तुर्की - गारंटर देशों- ने सीरिया की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर ध्यान देते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। अपने अंतिम वक्तव्य में, गारंटर-राज्यों ने सीरिया की संप्रभुता की सुरक्षा पर बल दिया, और सीरिया में 'डी-एस्कलेशन' क्षेत्रों (कम तीव्रता वाले क्षेत्रों) के निर्माण पर ज्ञापन के कार्यान्वयन की प्रगति का स्वागत किया। रूस, तुर्की और ईरानी राष्ट्रपतियों ने सीरिया में आतंकवाद के खिलाफ जंग में प्राप्त की गई उपलब्धियों, विशेष रूप से आईएसआईएल की हार और आईएसआईएल से सभी सीरियाई क्षेत्र की आसन्न मुक्ति का स्वागत किया। उन्होंने डीएईएसएच / आईएसआईएल, नुसरा फ्रंट और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित अन्य आतंकवादी संस्थाओं को अंततः खत्म करने और अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को अन्य देशों या क्षेत्रों में स्थानांतरित होने से रोकने के लिए अपना सहयोग बनाए रखने के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने हिंसा को कम करने की प्रगति को अपरिवर्तनीय बनाना सुनिश्चित करने हेतु समन्वित प्रयासों को जारी रखने की दिशा में अपने संयुक्त दृढ़ संकल्प की पुष्टि की।

तीनों गारंटरों ने 29-30 जनवरी, 2018 को सोची में सीरियाई समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के साथ सीरियाई राष्ट्रीय संवाद कांग्रेस की तैयारी और आयोजित करने के लिए नियमित रूप से बातचीत करने का संकल्प लिया और सीरियाई सरकार के प्रतिनिधियों और विपक्षों से सक्रियता के साथ सहयोग देने की अपील की, जो सीरिया के संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता और अविभाजक स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस सन्दर्भ में, तीनों देश 19-20 जनवरी 2018 को कांग्रेस आयोजित करने से पहले सोची में एक विशेष तैयारी बैठक बुलाएंगे।

तीन राष्ट्रपतियों ने कांग्रेस के प्रतिभागियों का निर्णय लिया, लेकिन उनका नाम नहीं बताया, जो सीरिया के अंदर और बाहर मौजूद विभिन्न विपक्षी समूहों की ओर से सीरिया के भविष्य के बारे में अपनी दृष्टि को रेखांकित करेंगे। सीरियाई सरकार ने कांग्रेस में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, लेकिन विपक्षी समूहों ने अभी तक अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। अंतिम वक्तव्य के अनुसार, तीनों नेता बंधकों की रिहाई पर एक कार्यदल का गठन करने और संघर्षग्रस्त देश में खदान हटाने पर सहयोग करने

के लिए भी सहमत हुए। बंधकों के संबंध में उठाए गए कदम का सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टाफ़न डी मिस्तुरा ने स्वागत किया।

अस्ताना वार्ता का आठवां दौर 22 नवंबर को मास्को में आयोजित सातवें दौर के अनुसरण में हुआ, जहां तीन राष्ट्रपतियों ने दिसंबर 2016 के अलेप्पो संकट के बाद रूस और तुर्की द्वारा आरम्भ की गई अस्ताना शांति प्रक्रिया की प्रगति और भविष्य पर चर्चा की। अपने संयुक्त वक्तव्य में, उन्होंने "देश की एकता को बहाल करने , और एक समावेशी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी, सीरिया द्वारा संचालित और सीरियाई मूल की प्रक्रिया के माध्यम से संकट का राजनीतिक समाधान प्राप्त करने में सीरियाई लोगों का समर्थन करने के लिए सहमति जताई , जिससे एक ऐसा संविधान बनेगा जिसमें सीरिया के लोगों का समर्थन हासिल होगा और संयुक्त राष्ट्र के उचित पर्यवेक्षण के अधीन सीरिया के सभी पात्र लोगों की सहभागिता के साथ मुक्त और निष्पक्ष चुनाव का आनंद लिया जा सकेगा।"[i]

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सीरिया में अस्ताना प्रक्रिया के तहत स्थापित 'डी-एस्कलेशन' क्षेत्रों (मानचित्र 1)[ii] का निर्माण, हिंसा को कम करने और मानवीय पीड़ा को दूर करने, शरणार्थियों के प्रवाह पर अंकुश लगाने और शरणार्थियों तथा आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को सुरक्षित वापस लौटने के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम शुरू करने में काफी हद तक दक्ष रहा है और इससे काफी मदद भी मिली है। उन्होंने स्वीकार किया कि "अस्ताना प्रारूप" और इसकी उपलब्धियां सीरिया में शांति और स्थिरता लाने का एक प्रभावी साधन बन गए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने समन्वित प्रयासों को जारी रखने का निर्णय लिया कि हिंसा को घटाने में की गई प्रगति अपरिवर्तनीय हो।

राज्य के प्रमुखों ने सीरिया की संप्रभुता , स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपनी कड़ी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और बल दिया कि किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त डी-एस्कलेशन क्षेत्रों के निर्माण से और सीरियाई संकट को हल करने के लिए की गई राजनीतिक पहल से सीरिया की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का शमन नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक और व्यापक अंतर- सीरियाई संवाद आयोजित करने के प्रति समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधियों और विपक्ष से अपील कि वे निकट भविष्य में सोची में आयोजित होने वाली सीरियाई राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन में रचनात्मक रूप से भाग लेने के लिए सीरियाई राज्य की संप्रभुता , स्वतंत्रता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता और अविभाजक स्वरूप के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे कांग्रेस की सफलता में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सहमत हुए। ईरान, रूस और तुर्की कांग्रेस के प्रतिभागियों से परामर्श करेंगे और सहमत होंगे। राष्ट्रपतियों ने यह आशा व्यक्त की कि ईरान , रूस और तुर्की के सहयोग से सीरियाई

संकट का समाधान करने में जो प्रगति हुई है, उससे क्षेत्र की समग्र स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जातीय और सांप्रदायिक विभाजन का खतरा कम होगा।[iii]

सातवें दौर के वार्ता की महत्वपूर्ण बिन्दुएँ

कज़ाख़स्तान मुख्य रूप से सभी हितधारकों के लिए अस्ताना संवाद का एक परस्पर रूप से स्वीकार्य सूत्रधार बन गया क्योंकि तुर्की के हवाई क्षेत्र को कथित तौर पर पार करने पर एक रूसी जेट को मारकर गिराए जाने के बाद, इसने तुर्की और रूस के बीच विवेकपूर्ण ढंग से सुलह करवाई थी। तुर्की की निर्माण कंपनियों ने कई परियोजनाओं में 21 बिलियन अमरीकी डॉलर तक का रकम निवेश किया है, जो दोनों देशों को व्यापार और कूटनीतिक संबंधों से जोड़ता है।[iv] कज़ाख के अधिकारी लगभग 300 कज़ाख लड़ाकों की वापसी पर चिंतित हैं जो इस्लामिक राज्य और अन्य आतंकी समूहों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सीरिया गए थे; और, वे उनकी वापसी पर नजर रखना चाहते हैं। [v] कज़ाख़स्तान ने अपने पहले के सोवियत दायरे से परे अपने संबंधों में विविधता लाने के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय राजनय बढ़ाया है ताकि यह रूस और अन्य शक्तिशाली देशों के बीच संतुलन बना सके। विश्व संघर्षों के प्रति एक स्वीकार्य मध्यस्थ के रूप में कज़ाख़स्तान का उदय एक ऐसा अतिरिक्त लाभ है , जिसका फायदा कज़ाख़स्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक पहुँच बढ़ाने के लिए उठा रहा है । कज़ाख़स्तान के राष्ट्रपति नुर्सुल्तान नाज़र्बायव ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन दोनों के साथ एक घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा है, जिससे उन्हें दोनों देशों के बीच समान आधार खोजने में मदद मिली है। अस्ताना संवाद एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है, जो विभिन्न हितधारकों - जैसे कि ईरान- नियंत्रित लड़ाकों, तुर्की समर्थित विपक्षी समूहों और सीरिया शासन को प्रभावित करते रूसी लोगों - एक स्थायी शांति के लिए आवश्यक रियायतें प्रदान करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन सीरियाई संकट सबसे जटिल संकटों में से एक है, जिसने पश्चिम एशियाई क्षेत्र को त्रस्त कर दिया है और इस खेल को जीतने के लिए कई खिलाड़ियों ने भाग लिया है। शांति प्रदान करने के लिए कज़ाख़स्तान के राजनय की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि कज़ाख़स्तान सरकार रूसी और ईरानी प्रभाव के बिना किस हद तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, जिन्होंने वास्तव में कज़ाख़स्तान को अपनी ओर से पहल करने के लिए बाध्य किया है।

कहा जाता है कि अस्ताना संवाद ने जिनेवा शांति प्रक्रिया को निष्प्रभावित कर दिया है, जिसमें अक्सर पक्षों के मध्य असहमति होती थी और जिसपर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी। अस्ताना संवाद ने सीरिया के राजनीतिक संक्रमण और शांति प्रक्रिया के लिए एक रोडमैप तैयार किया है जिससे सुरक्षा स्थिति सामान्य हो सकती है। इस संवाद में ऐसे छह प्रमुख बिन्दुएँ हैं जिन पर तीनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की है:

1. उस देश में शांति और स्थिरता , और इसकी संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित करना।
2. आईएसआईएस, जबाह अल-नुसरा और अन्य चरमपंथी समूहों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सहयोग।
3. डी-एस्कलेशन क्षेत्र में युद्ध विराम और स्थायी संचालन को मजबूत करना।
4. संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच विश्वास बढ़ाना।
5. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2254 के आधार पर समावेशी अंतर- सीरियाई संवाद आयोजित करना और सीरियाई राष्ट्रीय वार्ता कांग्रेस की घोषणा करना जिसमें सीरियाई जनसंख्या के सभी वर्गों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
6. कांग्रेस सीरिया के भविष्य पर चर्चा करेगी और सीरिया के लिए एक नया संविधान बनाने की स्थितियां बनाएगी, भविष्य के राज्य के लिए मानदंड परिभाषित करेगी और इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चुनाव आयोजित करवाएगी।

इस प्रकरण में, ईरान और तुर्की के राष्ट्रपतियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि संकट को हल करने के लिए उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें कितना लचीलापन है। ईरानी पक्ष आतंकवाद के खतरे को मुख्यतः उन ताकतों में देखता है जो असाद शासन के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं, जबकि तुर्की पक्ष इस खतरे को मुखर सीरिया-कुर्द स्वायत्त क्षेत्रों में सामना किए जा रहे खतरों के रूप में रेखांकित करता है , जो सीरिया के पूर्वोत्तर से लेकर अफरीन में पश्चिमी शहर तक , एक स्वतंत्र राज्य बनने की आकांक्षा में है। हालांकि, रूसी वक्तव्यों में स्पष्ट रूप से सीरिया-कुर्द "खतरे" और उसके भविष्य पर अस्पष्टता नज़र आ ती है, तब भी जब इसने सीरिया की एकता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा समर्थन किया है।

यह समझना आसान है कि तीनों नेताओं के लिए एक ऐसे देश में सभी के लिए जीत की स्थिति प्राप्त करना कितना मुश्किल है , जहां उनके हित अक्सर टकराते हैं। सीरिया में अमेरिकी नीति , जो सीरियाई कुर्द लड़ाकों को एकतरफा रूप से सशक्त बना रही और उन्हें हथियार उपलब्ध करवा रही है, तुर्क के आरोपों के अनुसार जो एक स्वतंत्र राज्य बनाने की योजना बना रहे हैं, क्षेत्रीय रूप से एकजुट सीरिया की नीति को आगे बढ़ाने का एक सामान्य केंद्र बन गया है। अपने एजेंडों में फर्क होने के बावजूद, रूस, ईरान और तुर्की सीरिया के लिए और साथ ही अपने लिए एक समाधान खोजने में सक्षम रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने वक्तव्य में कहा कि रूस , ईरान और तुर्की के प्रयासों ने "सीरिया के विघटन" को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के हाथों में पड़ने और मानवीय तबाही से बचने में

मदद की है। जैसा कि प्रो-असाद मध्यस्थ दावा करते हैं, लगता है कि रूस द्वारा निभाई गई भूमिका अब केवल "असाद शासन की रक्षा और सुरक्षा " ही नहीं रही है। रूसी संकट से बाहर निकलने के लिए एक रणनीति बनाने और किसी शर्त को माने बिना देश के लिए स्थायी शांति प्राप्त करने की बात करते हैं।

अस्ताना में सात दौर की बैठकों के बाद , एक राष्ट्रव्यापी युद्धविराम के अलावा, चार डी-एस्कलेशन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:[vi]

क्षेत्र 1: इदलिब प्रांत, साथ ही लताकिया प्रांत के उत्तरपूर्वी इलाके, अलेप्पो प्रांत के पश्चिमी इलाके और हामा प्रांत के उत्तरी इलाके।

क्षेत्र 2: उत्तरी होम्स प्रांत की रस्तन और तल्बिसेह परिवृत्ति।

क्षेत्र 3: उत्तरी दमिश्क देश का पूर्वी घोउटा।

क्षेत्र 4: जॉर्डन की सीमा के साथ सटा दक्षिणी क्षेत्र जिसमें डेरा और कुनेत्र प्रांत के कुछ हिस्से शामिल हैं

अस्ताना संवाद के सहमति अनुसार डी-एस्कलेशन क्षेत्र

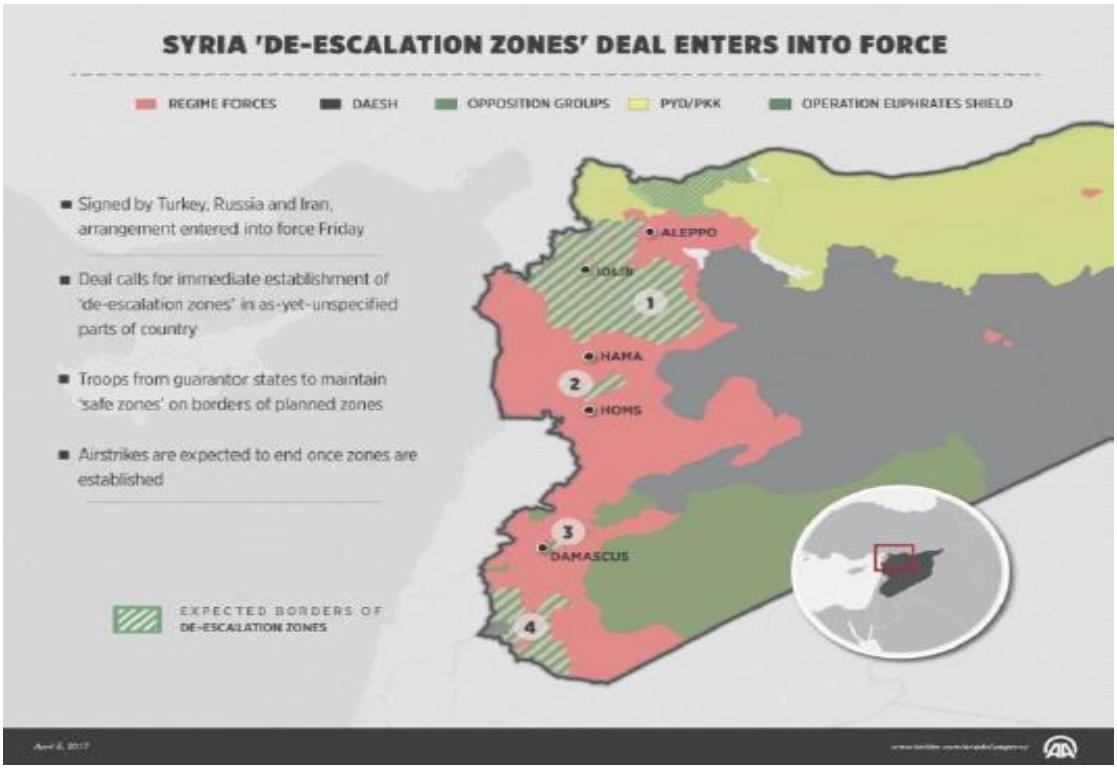

स्रोत: अनादोलु एजेंसी

इन चारों क्षेत्रों में हिंसा में भारी गिरावट देखी गई है, हालांकि अब भी क्षेत्र 3 में थोड़ी हिंसा जारी है। इन क्षेत्रों ने तुर्की और ईरान को गारंटरों की भूमिका नियुक्त की है, जो आतंकवादी समूहों की ओर से दीर्घकालिक युद्धविराम का दबाव बना रहे हैं। जुलाई 2017 में इसकी घोषणा होने के बाद से प्रक्रिया की सफलता ने संकट के प्रति एक राजनीतिक परिणाम लाने की नई आशा पैदा की है।

अस्ताना शांति प्रक्रिया की उत्पत्ति

कज़ाख़स्तान के राष्ट्रपति नुर्सुल्तान नाज़र्बायेव ने शुरुआत में अस्ताना को एक ऐसे स्थल के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे सीरिया के विपक्षों के बीच युद्धविराम वार्ता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। राजनयिक संवाद के माध्यम से संघर्ष को सुलझाने के लिए अस्ताना वार्ता के योगदान को संयुक्त राष्ट्र और कई विश्व अग्रणियों द्वारा मान्यता मिली है। अस्ताना प्रक्रिया जिनेवा प्रक्रिया के अनुपूरक है, जहाँ सीरिया के संघर्ष का शांतिपूर्ण और स्थिर समाधान सुनिश्चित करने के लिए दोनों साथ मिलकर काम करने का उद्देश्य रखते हैं।

अस्ताना प्रक्रिया तब अस्तित्व में आई जब दिसंबर 2016 में रूस और तुर्की ने कज़ाख़स्तान की राजधानी अस्ताना को सीरिया की शांति वार्ता आगे बढ़ाने के लिए एक नए स्थल के रूप में स्वीकृति प्रदान की। 20 दिसंबर 2016 को ईरान, तुर्की और रूस के विदेश मंत्रियों ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2254 के अनुसार, कज़ाख़स्तान के अस्ताना में सीरिया शांति वार्ता आयोजित करने की सहमति व्यक्त की । 23 दिसंबर 2016 को, सीरियाई विपक्षी प्रतिनिधिमंडल और सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने रूस, तुर्की और ईरान द्वारा प्रायोजित अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए अस्ताना में मुलाकात की। इस बैठक का शीर्षक 'सीरियाई समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक' था।

अस्ताना बैठक 30 दिसंबर, 2016 को हस्ताक्षरित युद्ध विराम को सुदृढ़ बनाने के इरादे से रखी गई थी। ये सीरिया के सशस्त्र विद्रोही गुटों और रूस, ईरान और तुर्की द्वारा समर्थित सीरियाई सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता थी , जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल मध्यस्थ और एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। इस वार्ता को पहली बार सीरियाई सरकार और सशस्त्र विपक्ष दोनों को शामिल करती वार्ता का श्रेय मिला है। अस्ताना शांति वार्ता के अन्य छह दौर[vii] के दौरान, जो मुख्य बिंदु तय किए गए थे, वे निम्नानुसार हैं - हाल के संवादों में, तीनों पक्षों ने उन उपायों पर सहमति व्यक्त की है जिसने जिनेवा प्रक्रिया की तुलना में अधिक विश्वसनीय शांति प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की है।

गारंटर राज्यों का तंत्र

क्योंकि रूस, तुर्की और ईरान पूरी तरह से अलग- अलग हितों की वजह से सीरिया के साथ जुड़े हैं , इसलिए एक त्रिपक्षीय तंत्र बनाने पर उनकी सहमति एकमात्र ऐसा प्रभावी तंत्र साबित हुई जो युद्धरत पक्षों को संवाद के परिणामों का सम्मान करने के लिए मजबूर कर सकते थे। गारंटर राज्यों (रूस, ईरान और तुर्की) ने आठ बैठकें की हैं जिनमें वे कुछ मुद्दों और क्षेत्रों पर सहमत हुए हैं , जो मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:

- सीरिया में युद्धविराम की अनुवीक्षा के लिए एक त्रिपक्षीय तंत्र स्थापित करना;
- विशिष्ट मुद्दों पर अस्ताना मंच पर बैठकें आयोजित करना।
- संयुक्त अनुवीक्षा समूह स्थापित करना, जिसके परिणाम संयुक्त राष्ट्र को सूचित किए जाएंगे;
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 2254 (2015) के प्रावधानों का निर्देश पालन करना;

मुख्य संदर्भ के रूप में जिनेवा और संयुक्त राष्ट्र

अस्ताना वार्ता में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जिनेवा प्रक्रिया पर पहले से चल रहे किसी भी टकराव या दोहराव से बचा गया। अधिकतर संवादों में, तीनों पक्ष जिनेवा प्रक्रिया का सम्मान करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हुए हैं:

- संघर्षरत पक्षों, सीरियाई विपक्ष और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे अंतर-सीरियाई वार्ता को गति देने का प्रयास करने के लिए उभरती हुई अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग करें और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित राजनीतिक प्रक्रिया तथा अन्य पहल को आगे बढ़ाएं, और ऐसा तात्कालिक आधार पर किया जाए; (14-15 सितंबर 2017)

राजनीतिक संवाद और सीरियाई राष्ट्रीय कांग्रेस

- अपनी अभिशंसा व्यक्त की कि सीरियाई संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है और इसे केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2254 को संपूर्ण रूप से लागू करने के आधार पर ही एक राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जा सकता है; (23-24 जनवरी 2017)

23-24 जनवरी, 2017 को सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार और अस्ताना के सशस्त्र विपक्षी समूहों के बीच वार्ता का समर्थन किया गया

- बल दिया गया कि वे आगामी सीरियाई राष्ट्रीय संवाद कांग्रेस को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में वार्ता प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में देखते हैं और ये

आपसी सहमति के आधार पर अंतर- सीरियाई समझौते को सुकर बनाएगा ; (21-22 दिसंबर 2017)

राजनीतिक संक्रमण

गारंटर राज्यों ने राजनीतिक संक्रमण पर विस्तार से चर्चा की और संक्रमण से संबंधित कई धाराओं पर सहमति व्यक्त की है जिनमें शामिल हैं:

- बंधकों और कैदियों के आदान-प्रदान पर एक कार्य समूह का प्रावधान
- सीरियाई संविधान पर एक कार्य समूह बनाने की संभावनाएँ
- उन्होंने अपनी ये अभिशंसा भी व्यक्ति की कि सीरियाई संघर्ष का समाधान केवल राजनीतिक साधनों से करना संभव है।
- गारंटर राज्यों ने अस्ताना प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया जो जिनेवा शांति वार्ता को सुकर बनाता है।
- संघर्षरत पक्षों, सीरियाई विपक्ष और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे अंतर-सीरियाई वार्ता को गति देने का प्रयास करने के लिए उभरती हुई अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग करें और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित राजनीतिक प्रक्रिया और अन्य पहल को आगे बढ़ाएं, और ऐसा तात्कालिक आधार पर किया जाए;
- यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों को जारी रखने के लिए संयुक्त दृढ़ संकल्प व्यक्त करना कि हिंसा घटाने में जो प्रगति हो रही है, वह अपरिवर्तनीय हो। वे देश की एकता को बहाल करने में सीरियाई लोगों की सहायता के लिए तत्काल और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करना, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 2254 (2015) के उपबंधों के अनुसार तथा एक समावेशी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी, सीरिया द्वारा संचालित और सीरियाई मूल की प्रक्रिया के माध्यम से संकट का राजनीतिक समाधान प्राप्त करना, जिससे एक ऐसा संविधान बनेगा जिसमें सीरिया के लोगों का समर्थन हासिल होगा और संयुक्त राष्ट्र के उचित पर्यवेक्षण के अधीन सीरिया के सभी पात्र लोगों की सहभागिता के साथ मुक्त और निष्पक्ष चुनाव का आनंद लिया जा सकेगा।" (21-22 दिसंबर 2017)

आतंक

तीनों पक्षों ने आतंकवादी समूहों पर अपने मतभेदों को भी कम किया है और मूल विरोधी सशस्त्र समूहों को आतंकवादी समूहों से अलग करने पर सहमति व्यक्त की है। अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में, तीनों राज्यों

की ओर से रूसी विदेश मंत्रालय ने सात सशस्त्र समूहों की पहचान की थी जिन्हें शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहचाना गया था। उन्होंने निम्न की सहमति भी दी:

- आईएसआईएल/ डीएईएसएच और अल-नुसरा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के प्रति अपने दृढ़ संकल्प को दोहराना और सशस्त्र सेना समूहों से उनसे अलग करना; (23-24 जनवरी 2017)
- आईएसआईएस और जबाह अल नुसरा जैसे आतंकवादी समूहों और सशस्त्र विपक्षी समू हों की अवस्थिति को दर्शाते हुए एक मानचित्र बनाना।
- बंधकों और कैदियों के आदान-प्रदान पर कार्यकारी समूह का प्रावधान और सीरियाई संविधान पर एक कार्य समूह की स्थापना करने की संभावना।
- सीरिया में आईएसआईएस और अन्य सक्रिय आतंकवादी समूहों के उन्मूलन पर बल देना; साथ ही संघर्षरत पक्षों के मध्य विश्वास बनाने की आवश्यकता पर बल देना।

डी-एस्कलेशन क्षेत्र एंड मानवीय सहायता

- उन्होंने इदलिब, होम्स, पूर्वी घोउटा, साथ ही डेरा और अल- कुनेत्र में चार डी- एस्कलेशन क्षेत्र बनाने और हिंसा को तुरंत समाप्त करने , मानवीय स्थिति में सुधार कर ने और सीरियाई अरब गणराज्य में संघर्ष के राजनितिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- गारंटर राज्यों ने युद्ध विराम व्यवस्था को मजबूत करने, इसके उल्लंघन को अस्वीकार्य बताने, साथ ही संघर्षरत पक्षों के मध्य वि श्वास-बनाने को बढ़ावा देने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की।
- 8 सितंबर 2017 को अंकारा में जिन मानचित्रों पर सहमति व्यक्त की गई थी, उसके आधार पर तीनों गारंटरों के डी-एस्कलेशन नियंत्रण बलों का डी-एस्कलेशन क्षेत्रों में सुरक्षा क्षेत्र में अस्थायी आधार पर डी-एस्कलेशन संयुक्त कार्य समूह द्वारा डी- एस्कलेशन नियंत्रण बलों की तैनाती के लिए तैयार किए गए विचारार्थ विषयों के अनुसार आवंटन।
- डी-एस्कलेशन क्षेत्रों में डी- एस्कलेशन नियंत्रण बलों की समन्वित गतिविधियों की ओर लक्षित संयुक्त ईरानी-रूसी-तुर्की समन्वय केंद्र का गठन।
- उन्होंने सीरिया में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के खनन के मुद्दे को भी संबोधित किया।

सीरिया की आंचलिक अखंडता और संप्रभुता

गारंटर राज्यों - ईरान, रूस और तुर्की - के प्रतिनिधिमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने सीरिया की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- गारंटर राज्यों ने सीरियाई अरब गणराज्य की संप्रभुता , स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की;
- गारंटर राज्यों के निर्णय संयुक्त रष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 2254 (2015) के उपबंधों द्वारा निर्देशित हैं;
- बल दिया कि किसी भी परिस्थिति में उप र्युक्त डी-एस्कलेशन क्षेत्रों के निर्माण से सीरियाई अरब गणराज्य की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर नहीं पड़नी चाहिए।

सीरिया में क्या किसके नियंत्रण में है

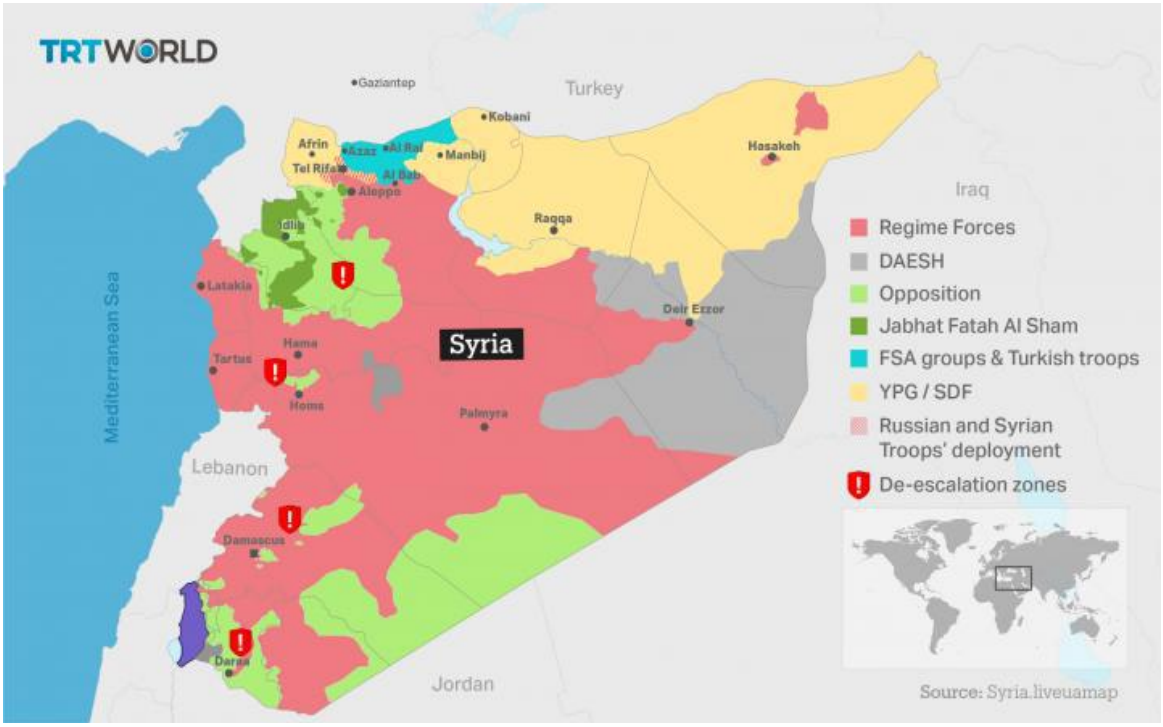

स्रोत: टीआरटी वर्ल्ड टीवी

2011 के बाद से, [viii] सीरियाई संघर्ष को समाप्त करने के लिए कई योजनाओं और समझौतों का विस्तार किया गया था, और इन पहलों के संपरिधान को अक्सर सीरियाई शांति प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। 2012 में, संयुक्त राष्ट्र ने P5 के नेतृत्व के तहत जिनेवा सम्मेलन का समर्थन किया। उस सम्मेलन का परिणाम एक ऐसी शासी सूचना जारी करना था , जिसमें सीरिया की राजनीतिक संघर्ष को सुलझाने के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में बताया जाए। हालांकि, इस दस्तावेज़ में उन पक्षों की पहचान

नहीं की जा सकी, जिन्हें एक संभावित संक्रातिक सरकार में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई विपक्षी आंदोलन रहे हैं जिनकी मान्यताएं और प्रेरणा अलग-अलग है।

इस बीच, जनवरी 2013 में, राष्ट्रपति असाद ने एक अपनी शांति योजना पेश की जिसमें एक राष्ट्रीय सुलह सम्मेलन, एक नई सरकार और एक नया संविधान शामिल था , जिसे विपक्ष ने अस्वीकार कर दिया।

जिनेवा प्रक्रिया

जनवरी 2014 में, संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया पर जिनेवा II सम्मेलन आयोजित किया, जहां इसने असाद सरकार और कुछ सबसे प्रमुख विपक्षी समूहों (सीरियाई राष्ट्रीय गठबंधन) को बातचीत की मेज पर एक साथ लाने की कोशिश की। इस शांति प्रक्रिया में , दोनों पक्ष शामिल थे , लेकिन यह किसी भी ठोस समाधान पर नहीं पहुँच सका क्योंकि राष्ट्रपति असाद ने विपक्ष की मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगले दौर की वार्ता वियना में हुई। यह तब हुआ जब रूसी सेना ने असाद सरकार की मदद करना शुरू कर दिया था। इस बैठक के मुख्य भागीदार अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की थे, तथा ये सभी देश असाद के भविष्य और विपक्षी समूहों , विशेष रूप से कुर्द के व्यवहारों के बारे में निश्चित तौर पर अलग-अलग दृष्टिकोण रखते थे। हालाँकि, इस बैठक में सी रिया की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं था। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, चीन, मिस्र, ओमान, कतर, जॉर्डन, लेबनान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन के अंत में, प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की कि सीरियाई संघर्ष का समाधान राजनयिक होना चाहिए, लोगों और सीरिया की अखंडता का सम्मान होना चाहिए, और यह कि इस्लामिक राज्यों को हराया जाना चाहिए। राजनीतिक संक्रमण योजना को सफल बनाने की गारंटी के लिए संयुक्त राष्ट्र को सरकार और सीरिया ई विपक्ष के बीच मध्यस्था के लिए आमंत्रित किया गया था। विपक्षी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष समूह या व्यक्तियों के नाम ज्ञात नहीं थे। 14 नवंबर को, वियना में दूसरे दौर की वार्ता हुई, जिसमें 30 अक्टूबर को मौजूद देशों और संगठनों और अरब लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस समूह को "सीरिया अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह" (आईएसएसजी) के नाम से जाना जाने लगा।

देशों ने सीरियाई बुनियादी अवसंरचनाओं के विनाश को समाप्त करने के साथ- साथ सीरियाई लोगों की पीड़ा को कम करने के आग्रह के बारे में बात की। वे सभी इस बात पर सह मत थे कि देश में युद्ध विराम की स्थापना तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में , यह भी तय किया गया कि सीरिया में 18 महीने के भीतर एक नए संविधान के मसौदे पर केंद्रित चुनाव होंगे, और यह कि सीरिया सरकार

और विपक्षी समूहों के बीच शांति वार्ता की शुरुआत की समय सीमा 1 जनवरी 2016 तक की होगी। वार्ता में विपक्षी समूहों का प्रतिनिधित्व करने की कसौटी ये थी कि यह विपक्षी समूहों के व्यापक संभावित स्पेक्ट्रम से होना चाहिए , जिन्हें सीरियाई लोगों द्वारा चुना जाएगा और जो उनके लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आईएसएसजी ने एक नया संविधान तैयार करने के लिए सीरिया सरकार और विपक्षी दलों के मध्य एक साझा आधार खोजने पर भी बल दिया।

फरवरी 2016 को जिनेवा III हुआ। अप्रैल 2016 में सीरिया में एक संक्रातिक सरकार बनाने और इस्लामिक राज्य को हराने के अलावा , प्राथमिक लक्ष्य के रूप में युद्ध विराम की स्थापना करना एक उद्देश्य था। इस बैठक में , विपक्षी दल उच्च वार्ता समिति (एचएनसी) की छत्रछाया तले आए। हालांकि इसके परिणाम सफल नहीं रहे, फिर भी इस बैठक के कुछ दिनों बाद , आईएसएसजी, अमेरिका और रूस ने युद्धविराम के लिए एक कार्य बल का गठन किया। युद्ध विराम को बनाए रखा गया और अप्रैल 2016 में संसदीय चुनाव संचालित हुए जिसे एचएनसी ने विधि विरुद्ध घोषित कर दिया।[ix] राष्ट्रपति असाद चुनाव जीत गए।

जिनेवा III का तीसरा दौर अप्रैल में हुआ जो असफल रहा। युद्ध विराम के बावजूद हिंसा जारी रही। कुर्द के प्रतिनिधियों को इस बैठक से बाहर रखा गया था।

फरवरी 2017 में, जिनेवा IV का चौथा दौर शुरू हुआ। जिनेवा IV तकनीकी वार्ता के चार सेटों पर केंद्रित था : जवाबदेह शासन; संविधान; चुनाव; और, आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा प्रशासन।[x] फरवरी 2017 में, जिनेवा V हुआ, जहां युद्धरत पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 2254 पर आधारित वार्ता के लिए सहमत हुए, जिसने जवाबदेह शासन, एक नए संविधान और 18 महीने के भीतर संयुक्त राष्ट्र-पर्यवेक्षित चुनावों के आधार पर एक राजनीतिक संक्रमण की नींव रखी। मई में, जिनेवा VI आयोजित हुई और पिछले वार्ता के दौरान जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी, इस वार्ता में उन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं हुई , और इस तरह ये भी असफल रहा । जिनेवा वार्ता का सातवाँ दौर भी जुलाई में आयोजित हुआ लेकिन ये भी असफल रहा । नवीनतम जिनेवा वार्ता अस्ताना प्रक्रिया के बाद नवंबर में हुई। आठवां दौर भी विफल रहा क्यों कि संक्रमण के दौरान असाद की भूमिका पर विपक्ष की मांगों के कारण असाद सरकार वार्ता छोड़कर चली गई थी।

सऊदी अरब की भूमिका

अस्ताना और जिनेवा की वार्ता के अलावा , सऊदी अरब ने भी शांति प्रक्रिया में सहायता प्रदान की है। शांति वार्ता का पहला दौर रियाद में हुआ जहां विपक्षी दलों ने सीरिया के भाग्य के बारे में चर्चा करने और असाद सरकार से बात करने के लिए अपना एजेंडा तैयार करने के लिए दिसंबर 2015 में मुलाकात

की। रियाद छत्रछाया के अधीन आयोजित बैठकों का एजेंडा सीरिया में शक्तियों के संक्रमण और राष्ट्रपति असाद को हटाने के मुद्दों पर विपक्षों के मध्य एक आम दृष्टिकोण खोजना था। रियाद वार्ता सभी विपक्षी समूहों को एक-साथ लाने और सीरिया के भविष्य के लिए एक आम दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए थी। 2015 की बैठक के दौरान, "संक्रमणकालीन अवधि" के विषय में बातचीत की शुरुआत में ही एक समूह ने राष्ट्रपति असाद से पद त्यागने की अपील की, जिससे "बहुलवादी शासन के माध्यम से एक लोकतांत्रिक तंत्र का निर्माण होगा जो सभी क्षेत्रों के सीरियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करता है "।[xi] दूसरी बैठक में, जो नवंबर 2017 में हुई, समूह ने 'रियाद 2-शासकीय सूचना' को अपनाया, जिसे राष्ट्रपति असाद को हटाने और संक्रमणकालीन अवधि के दौरान सीरिया के शासन में उन्हें शामिल ना करने की लगातार मांग के कारण सीरिया सरकार ने अस्वीकार कर दिया था।[xii]

विभिन्न विपक्षी समूह

चूंकि विपक्ष और शासन के बीच का ये युद्ध, क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए ए क अंतर-विपक्षी आतंकवादी समूहों की लड़ाई में बदल गया, इसलिए सीरियाई विपक्ष कमजोर हो गया और शासन के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहने और अपने एजेंडे में सुसंगत रहने की क्षमता ख़त्म हो गई। अब तक, कुछ ऐसे समूह भी हैं जो रूस से प्रभावित हैं जिन्हें "मॉस्को प्लेटफ़ॉर्म" कहा जाता है, जो बशर अल असाद के भविष्य के मुद्दे को किसी भी चर्चा का हिस्सा बिलकुल भी नहीं बनाना चाहते हैं, जबकि उच्च वार्ता परिषद और अन्य समूह स्पष्ट रूप से असाद के जाने की समय सीमा की वकालत कर रहे हैं । 2014 में काहिरा प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण हुआ था, कुछ ऐसे समूहों द्वारा जो सीरियाई सरकार और पूर्व मंत्री जिहाद मक्दिसी के करीबी थे, जो चाहते थे कि असाद संक्रमणकालीन अवधि में एक निश्चित समय तक बने रहें।[xiii] समूह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए।[xiv]

सीरियाई राष्ट्रीय परिषद, जो एकमात्र ऐसा समूह रहा है जो सीरिया के विपक्षी समूह के लिए उच्चतम और सबसे समावेशी समूह के रूप में अपनी एकता बनाए रखने में सक्षम है , और "काहिरा प्लेटफ़ॉर्म" का संबंध कठिन रहा है । एसएनसी के उपाध्यक्ष , हिशम मारवाह ने 20 मई 2015 को आयोजित काहिरा सम्मेलन पर कुछ विपक्षी समूहों को शामिल ना करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को सीरियाई क्रांति के सिद्धांतों को नहीं त्यागना चाहिए और राष्ट्रपति असाद को हटाने की मांग पर एकजुट होना चाहिए। [xv] जिसके परिणामस्वरूप, मॉस्को और काहिरा प्लेटफार्मों की बुनियाद में काफी समानता है, जबकि रूसी सैन्य हस्तक्षेप शुरू होने के बाद से उच्च वार्ता परिषद और एसएनसी ज्यादातर अलग-थलग बने हुए थे । लेकिन युद्ध के मैदान में, रूसी और असाद के अन्य समर्थक गुटों में विश्वसनीयता की गंभीर समस्या है। हाल के महीनों में , जब यमन में सऊदी-संचालित सैन्य हस्तक्षेप में मिस्र के लो-प्रोफाइल सैन्य भागीदारी के मुद्दे की वजह से सऊदी अरब और मिस्र के

संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे , तब सऊदी अरब ने एक बार फिर से सीरिया के विपक्षी नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया था।

सामने आते रुझान

विभिन्न मंचों पर होने वाली विभिन्न शांति वार्ताओं का एक ही लक्ष्य है , अर्थात सीरिया की संकट के लिए एक शांतिपूर्ण संक्रमण का हल खोजना। सभी पक्षों के विवाद का मुद्दा राष्ट्रपति असाद की भूमिका के बारे में है, जो संघर्षरत दलों को एक ही छत्र के नीचे आने और संकट को हल करने की अनुमति नहीं देता है। क्षेत्रीय शक्तियों समेत बाहरी शक्तियों ने साथ मिलकर काम करने की कोशिश की है , उदाहरण के लिए, ईरान और तुर्की का एक साथ आना, जो कुछ समय पहले तक विपक्षी बने हुए थे। अंकारा और तेहरान के अलावा, रूस और सऊदी अरब ने भी साथ आने के संकेत दिए हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान और तुर्की लगातार हिंसा और संकट से बढ़ती सैन्य और मानवीय देनदारियों से थक चुके हैं। सुन्नी क्षेत्रीय शक्ति ईरान को गहरे संदेह की निगाह से देखते हैं , जो केवल ईरान को अपने शिया मिलिशिया के ज़रिए "विस्तारवादी सांप्रदायिक प्रभाव" को अग्रसर करते एक शिया शक्ति के रूप में देखते हैं।[xvi] सीरियाई संकट का संप्रदायीकरण बहुत गहरा और निर्विवाद है , जिस तरह 2015 में असाद शासन को आसन्न पतन से बचाने के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया ने भाग लिया था। सुन्नी शक्तियों और विपक्षी समूहों ने ईरान और उसके मिलिशिया पर एक नियोजित जनसांख्यिकीय परिवर्तन करने का आरोप लगाया था , ताकि राजनीतिक प्रक्रिया के परिणाम असाद के पक्ष में जाए।[xvii] ईरान ने अपनी तरफ से, “सीरिया के वैध सरकार की अनुमति के बिना सीरिया के क्षेत्र में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति" और सऊदी-सलाफी चरमपंथी ताकतों पर उंगली उठाई।[xviii] क्षेत्रीय शक्तियों के मध्य व्याख्यानों की जंग अटूट रूप से जारी रही , हालांकि ये जंग अधिकतर ईरान के खिलाफ थी। तेहरान को भी अपने देश में नागरिकों का प्रकोप सहना पड़ रहा है , जो हाल ही में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन से स्पष्ट होता है। ईरानियों ने हिजबुल्लाह समूह (जो सीरिया में सक्रिय है) के लिए ईरान के समर्थन और सीरिया के लिए देश के समर्थन के संबंध में अपना असंतोष और आक्रोश दिखाया।

सीरियाई संकट ने विपक्षी शिविरों, जैसे कि रूस और सऊदी अरब एक साथ कर दिया है। शुरुआत में, सऊदी अरब ने दावा किया कि असाद के पक्ष में रूस की मजबूत सैन्य समर्थन के बावजूद उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा। हालांकि, अलेप्पो की जीत ने रियाद का सुर बदल दिया। तब से, सऊदी अरब ने राष्ट्रपति असाद को पद से हटाने की मांग करना और सीरिया में रूसी सेना की भूमिका की आलोचना करना बंद कर दिया है। रुख में आया ये बदलाव इस हद तक स्पष्ट है कि रूस और सऊदी अरब ने विपक्षी दल को एकजुट करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है।[xix]

सऊदी अरब के राजा ने सात दशकों में पहली बार रूस का राजकीय दौरा किया। तब से , सीरियाई संकट पर रूसी संभाषण को, सैन्य जीत द्वारा सीरिया पर पूर्ण रूप से कब्ज़ा करने के बजाय अधिक मैत्रीपूर्ण और बातचीत कर निकाले गए परिणाम के पक्ष में होता देखा जा सकता है , जैसा कि बशर अल असाद और उनके ईरान समर्थित आतंकवादी सहयोगियों ने दावा किया गया था।[xx]

सीरिया में रूस की सफलता

सीरिया संकट में रूस एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है। यह सैन्य शक्ति के रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से (इसके पश्चिमी नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के बावजूद) और कूटनीतिक रूप से अपनी शक्ति को प्रक्षेपित करने में सक्षम था। कैस्पियन सागर से मिसाइल छोड़ने के बाद से लेकर सीरिया में तार्तुस के बाद दूसरा सैन्य बेस सुरक्षित करने और आईएस को नष्ट करने के बारे में हाल ही दावा करने तक, रूस सीरिया में गृह युद्ध को समाप्त करने और साथ ही देश के भीतर आतंकवादी समूहों के उन्मूलन के लिए एक समझौते पर पहुंचने के प्रयास में अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की जैसी वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों का प्रबंधन करने में सक्षम था। रूस तुर्की को अपने शिविर में लाने में सक्षम रहा, जिस पर आतंकवादी समूह जबाह अल नुसरा का समर्थन करने का आरोप था। रूस और तुर्की के बीच इस संबंध में दिलचस्प बात यह है कि तुर्की ब्लैक सी में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के साथ-साथ उसके पास नाटो रूपक हुकुम का इक्का भी है , जिसे अंकारा मास्को के खिलाफ उपयोग कर सकता है। उसी समय, मास्को भी कुर्दों और ग्रीक साइप्रस के समर्थन के रूप में तुर्की के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

जॉर्डन, अमेरिका और इजरायल की मदद से बने डी-एस्कलेशन क्षेत्र भी रूस और ईरान के बीच मजबूत संबंधों के परिप्रेक्ष्य को सामने लाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्को जॉर्डन और इजरायल जैसे देशों को शांत करने में सक्षम रहा है जिसके तेहरान के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं।

जिस तरह से अस्ताना संवाद शुरू हुआ और आगे बढ़ा है, उससे स्पष्ट ये पता चलता है कि रूस ने अन्य हितधारकों को शामिल करने के लिए रणनीति बनाई है, जो जिनके साथ मिलकर रूस मध्य पूर्व क्षेत्रों में अपनी पहुँच विस्तृत करने की आकांक्षा रखता है । अस्ताना वार्ता के सातवें दौर से ठीक पहले , रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प , सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल, इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू , मिस्र गणराज्य के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी और कतर राज्य के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत करके विश्व भर में तपेदिक राजनयिक पहुँच कायम करने की कोशिश की। अस्ताना शिखर सम्मेलन के सातवें दौर से ठीक एक दिन पहले, सीरियाई राष्ट्रपति असाद पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए अघोषित दौरे पर सोची पहुंचे ,

सूचना के अनुसार जिसमें राष्ट्रपति असाद को राजनीतिक संकटों को शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने और संवैधानिक सुधार करने, तथा संयुक्त राष्ट्र-पर्यवेक्षित मुक्त चुनाव [xxi] (दोनों राष्ट्रपति और संसदीय [xxii]) करवाने के सिद्धातों के प्रति कटिबद्धता ली थी ।[xxiii] असाद के वक्तव्य को, राष्ट्रपति असाद समेत समस्त दलों द्वारा सीरिया के लिए पुतिन की योजना की अभिस्वीकृति के रूप में देखा गया। राष्ट्रपति असद सहित सभी दलों द्वारा सीरिया में पुतिन की योजनाओं के समर्थन के रूप में देखा गया था। उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जो शांति और संघर्ष का समाधान चाहता है।[xxiv] वार्ताओं के प्रकाशित लेख के अनुसार , बशर अल असाद ने "आतंकवाद" के खिलाफ लड़ाई को एजेंडे के शीर्ष पर रखने की कोशिश की और चेतावनी दी कि इस तथ्य की उपेक्षा करने से भविष्य में समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। हालांकि, राष्ट्रपति पुतिन ने राजनीतिक समझौता करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया।[xxv]

रूस न केवल अल्पावधि में, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वह संकट में शामिल सभी पक्षों - संघर्ष में सम्मिलित आंतरिक दलों के साथ-साथ क्षेत्रीय शक्तियों दोनों, को संतुलित करने का प्रयास करेगा। हाल ही में, रूस और सीरिया ने तार्तुस और खेमिम एयर बेस के सैन्य बेस का पट्टा 2092 तक विस्तृत किया।[xxvi] रूस ये पट्टा रखने की कोशिश करेगा और सीरिया के भविष्य के बारे में बातचीत करने की स्थिति में आएगा। इसने अतीत में कहा है कि यह राजनीतिक संक्रमण सहित सीरियाई लोगों के फैसले का समर्थन करता है , जिसका मतलब है एक ऐसा सीरिया जिसमें राष्ट्रपति असाद के कोई जगह नहीं है। भविष्य में, क्रेमलिन सीरिया की सरकार के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध को बरकरार रखेगा, फिर सत्ता में चाहे जो कोई भी हो।

विचारों का निष्कर्ष

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर सीरिया में अपनी भूमिका को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और अस्ताना शिखर सम्मेलन से मिलती तारीखों पर रियाद में पूरे सीरियाई विपक्ष को इकट्ठा किया। रियाद वार्ता से एक स्पष्ट संदेश मिलता है, जो यह है कि अगर सऊदी अरब की इच्छाओं को ध्यान में रखा गया, तो सऊदी अरब रूसी योजनाओं में साथ देने के लिए तैयार है। सीरियाई विपक्ष के प्रमुख नेता होने के नाते, रियाद हिजाब और अन्य लोगों ने रियाद वार्ता से पहले ही अपने इस्तीफे की घोषणा की, रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव इस घोषणा का स्वागत करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इस चाल को “मुख्य भूमिका निभाने में कट्टरपंथी विपक्षों की कदम वापसी ” कहा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस "इस संबंध में सऊदी अरब द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन करेगा। "[xxvii] रूसी कूटनीति, क्योंकि यह अंतिम परिणामों में अधिक से अधिक सुन्नी शक्तियों को शामिल करने की

कोशिश करता है, ने ईरान को अपने सैन्य बलों को एक राजनीतिक प्रक्रिया के लिए राजी कराने के लिए दबाव डाला है।[xxviii]

रूस, ईरान और तुर्की के बीच नवंबर की वार्ता ने सभी विपक्षी दलों के बीच सहमति की उम्मीद जगाई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन , सीरियाई राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सीरिया में शांति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 2254 की परिकल्पना अनुसार सीरिया में शांति और स्थिरता कायम करने , आतंकवाद के उन्मूलन और शरणार्थियों की वापसी समेत सीरिया के राजनितिक और उप-आर्थिक पहलुओं पर सर्वसम्मति प्राप्त की गई थी।

सीरिया में संघर्ष के समाधान के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। पुनर्निर्माण की लागत बहुत अधिक होने वाली है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रत्येक हितधारक के समर्थन की आवश्यकता होगी।

*****

डॉ इंद्राणी तालुकदार और डॉ ओमैर अनास आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली में रिसर्च फेलो हैं।

अस्वीकरण: ये विचार लेखक के हैं और परिषद के नहीं।

अंत टिप्पण

---

iJoint statement by Presidents of Iran, Russia and Turkey", President of Russia, November 22, 2017. http://en.kremlin.ru/supplement/5256 (Accessed on 23 November 2017).

iiIn the eastern Ghouta, in certain parts in the north of Homs province, in Idlib province and certain parts of the neighboring Latakia, Hama and Aleppo provinces and also in certain parts of southern Syria. https://www.rt.com/news/403428-deescalation-zone-syria-russia/

iiiJoint statement by Presidents of Iran, Russia and Turkey", President of Russia, op.cit.

iv Ministry of Foreign Affairs, Turkey, Relations between Turkey and Kazakhstan, http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-kazakhstan.en.mfa

vSamuel Ramani, 24 December 2016, What Does Kazakhstan Have at Stake in Syria?, The Diplomat https://thediplomat.com/2016/12/what-does-kazakhstan-have-at-stake-in-syria/

vi"Syria's 'de-escalation zones' explained" ,Al Jazeera, 4 July 2017 http://www.aljazeera.com/news/2017/05/syria-de-escalation-zones-explained-170506050208636.html viiIn the February 2017, Astana talks the representatives from the Syrian government and armed Syrian opposition groups, with the United Nations, the US and Jordan as observers were included. "Factsheet on the Astana Process", The Ministry of Foreign Affairs Republic of Kazakhstan, http://mfa.gov.kz/en/content-view/kratkaa-spravka-po-astaninskomu-processu (Accessed on December 15, 2017).

viiiDouglas de Quadros Rocha, Isabela Souza Julio and Patrícia Graeff Machry, "Peace Talks on the Syrian Conlfict", Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), v.1 n.1, July 2016. https://www.ufrgs.br/nerint/wp-content/uploads/2016/07/Boletim-v1n1-peacetalkssyria.pdf (Accessed on January 9, 2017). ix"Syria's HNC against letting Kurdish PYD side with opposition at Geneva talks", Ekurd. Net, March 21, 2016. http://ekurd.net/syria-hnc-against-kurdish-talks-2016-03-21 (Accessed on January 12, 2017). xThe Geneva process has never graduated beyond indirect talks, in which regime and opposition delegations meet with de Mistura's team, not with each other. Sam Heller, "Geneva Peace Talks Won't Solve Syria—So Why Have Them?" TCF, June 30, 2017. https://tcf.org/content/report/geneva-peace-talks-wont-solve-syria/ (Accessed on January 6, 2018). xiHussein Ibis, "Riyadh was an important step for the Syrian crisis", The National, December 12, 2015. https://www.thenational.ae/opinion/riyadh-was-an-important-step-for-the-syrian-crisis-1.99251 (Accessed on January 9, 2017). xii"Top Syrian negotiator rejects Riyadh-2 communiqué", The Iran Project, December 1, 2017. http://theiranproject.com/blog/2017/12/01/top-syrian-negotiator-rejects-riyadh-2-communique/ (Accessed on January 9, 2017). xiii Bassel Oudat, Opposition contradictions in Syria, http://weekly.ahram.org.eg/News/22295.aspx

xiv Syria's opposition, divided and varied, to get a new face 22 November 2017 https://apnews.com/1537eedc82a047838f415c0757f9c563

xv Syrian opposition group boycotts Cairo peace talks, Al Araby https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/5/20/syrian-opposition-group-boycotts-cairo-peace-talks

xvi Afshon Ostovar, 30 November 2016, Carnegeie Endowment http://carnegieendowment.org/2016/11/30/sectarian-dilemmas-in-iranian-foreign-policy-when-strategy-and-identity-politics-collide-pub-66288

xviiThe Guardian 14 September 2017 Iran repopulates Syria with Shia Muslims to help tighten regime's control https://www.theguardian.com/world/2017/jan/13/irans-syria-project-pushing-population-shifts-to-increase-influence.

xviiiJoint statement by Presidents of Iran, Russia and Turkey", President of Russia, op.cit. xix"Russia working with Saudi Arabia to unify Syrian opposition: Lavrov", Reuters, November 24, 2017. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-syria/russia-working-with-saudi-arabia-to-unify-syrian-opposition-lavrov-idUSKBN1DO1JO (Accessed on January 12, 2018).

xxMK Bhadrakumar, Asia Times 22 August 2017, Assad lays down new rules in winner-takes-all Syrian future http://www.atimes.com/article/assad-lays-new-rules-winner-takes-syrian-future/

xxiThe Syrian Diaspora (who will be eligible) will also be able to participate in the election.

xxii"Telephone conversation with US President Donald Trump", President of Russia, November 21, 2017. http://en.kremlin.ru/events/president/news/56143 (Accessed on November 24, 2017).

xxiii"Syrian President Bashar al-Assad made a working visit to Russia", President of Russia, November 20, 2017. http://en.kremlin.ru/events/president/news/56135 (Accessed on November 23, 2017).

xxivIbid.

xxvIbid.

xxvi"Putin Asks Lawmakers to Expand Russia's Navy Presence in Syria", The Moscow Times, December 13, 2017. https://themoscowtimes.com/news/putin-asks-lawmakers-to-expand-russias-navy-presence-in-syria-59928 (Accessed on January 12, 2018).

xxviiRussia says retreat of Syrian opposition figures good for peace 21 November https://www.reuters.com/article/mideast-crisis-syria-hnc-russia/russia-says-retreat-of-syrian-opposition-figures-